



राजस्थान समसामयिकी
सितंबर-नवम्बर
2020



© 2020 All Rights Reserved with RAJRAS Ventures LLP

This PDF eBook is only for personal reference. No part of this eBook (PDF) may be reproduced or transmitted by any form or by any means electronic or mechanical including printing, photocopying or recording or by any information storage and retrieval system or used in any manner without written permission from RajRAS Ventures LLP. RajRAS Ventures LLP may take legal action, file for criminal infringement & seek compensation for the loss.

Disclaimer: RajRAS Ventures LLP has obtained the information contained in this work from sources believed to be reliable. Care has been taken to publish information, as accurate as possible. RajRAS Ventures LLP nor its authors guarantee the accuracy or completeness of any information published herein, and neither RajRAS Ventures LLP nor its authors, affiliates, publishers or any other party associated with RajRAS Ventures LLP shall be liable or responsible for any errors, omissions or damages arising out of use of this information. RajRAS Ventures LLP and its authors are just making an attempt to provide information and not attempting to offer any professional services.

All disputes will be subject to Udaipur, Rajasthan Jurisdiction.

INDEX

चर्चित व्यक्ति.....	1
दिवस.....	10
चर्चित स्थान.....	11
पर्यावरण	18
सरकारी परियोजनायें.....	21
सामान्य करंट अफेयर्स.....	27
सरकारी apps एवं पोर्टल.....	43

चर्चित व्यक्ति

पुरस्कार

अशोक मेनारिया

अशोक मेनारिया को 6 सितम्बर 2020 को प्रदेश के प्रतिष्ठित क्रिकेट पुरस्कार "मथुरादास माथुर अवार्ड 2019-2020" से सम्मानित किया गया।

- मथुरादास माथुर अवार्ड 2019-2020 सीनियर वर्ग - **अशोक मेनारिया**
- मथुरादास माथुर अवार्ड 2019-2020 जूनियर वर्ग - **जीतेश पटेल**
- मथुरादास माथुर अवार्ड 2019-2020 सब-जूनियर वर्ग - **साहिल भास्कर**

गुलाब कोठरी

2 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर ओस्लो नार्वे की संस्था भारतीय-नार्वेजीय सूचना एवं संस्कृतिक फोरम की ओर से पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठरी को समाजसेवा एवं विश्व शांति में योगदान व लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

इस श्रेणी में अन्य सम्मानित होने वालों में गोवा की पूर्व राज्यपाल एवं लेखिका मृदुला सिन्हा, ओस्लो के समाजसेवी पत्रकार यालमार शेलांद, नॉर्वे एवं यूनाइटेड किंगडम के वरिष्ठ समाजसेवी और राजनीतिज्ञ वीरेन्द्र शर्मा (लंदन) को सम्मानित किया गया।

रोहित कुमार सिंह

11 अक्टूबर, 2020 को लोकनायक जयप्रकाश जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अध्ययन विकास केन्द्र ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी ACS रोहित कुमार सिंह को सर्वोच्च पुरस्कार (excellence award) से सम्मानित किया।

- केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया।

- रोहित कुमार सिंह को यह पुरस्कार कोरोना महामारी के दौरान उनके द्वारा किए गए सर्वश्रेष्ठ प्रबन्धन के लिए दिया गया है।
- रोहित सिंह प्रदेश के पहले एसीएस है, जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

नियुक्तियां

गोपाल सैनी

- अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित ओलम्पियन धावक गोपाल सैनी को राष्ट्रीय खेल विश्विद्यालय इम्फाल, मणिपुर द्वारा सदस्य नियुक्त किया गया है।
- इस पद पर सैनी का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

आयुष मनी तिवारी

तमिलनाडु कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आयुष मनी तिवारी को सीमा सुरक्षा बल (BSF) राजस्थान फ्रंटियर का नया आईजी नियुक्त किया गया है। उन्होंने निवर्तमान फ्रंटियर आईजी अमित लोढ़ा से चार्ज लिया है।

प्रोफ़ेसर राजीव जैन

9 सितम्बर 2020 को राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र द्वारा प्रोफ़ेसर राजीव जैन को राजस्थान विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है।

प्रोफ़ेसर भागीरथ सिंह

9 सितम्बर 2020 को राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र द्वारा प्रोफ़ेसर भागीरथ सिंह को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का कुलपति नियुक्त किया गया है।

बालेन्दु शर्मा दाधीच

14 सितंबर 2020 को हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट में कार्यरत वरिष्ठ तकनीकविद और पूर्व संपादक बालेन्दु शर्मा दाधीच को हिंदी में श्रेष्ठ लेखन के लिए इस वर्ष के 'राजभाषा गौरव' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

उन्हें यह पुरस्कार हिंदी दिवस के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रदान किया गया। बालेन्दु शर्मा को यह पुरस्कार उनकी पुस्तक 'दिव्यांगों के लिए तकनीक' के लिए प्रदान किया गया है। यह इस विषय पर हिंदी की पहली पुस्तक है।

श्री ओम थानवी

22 सितंबर 2020 को राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र ने महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के कुलपति का अतिरिक्त प्रभार हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के कुलपति श्री ओम थानवी को सौंपा है।

श्रीमती रोली सिंह

8 अक्टूबर 2020 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1994 बैच की वरिष्ठ आई.ए.एस.अधिकारी श्रीमती रोली सिंह ने नई दिल्ली के बीकानेर हाउस स्थित राजस्थान के आवासीय आयुक्त कार्यालय में प्रमुख आवासीय आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है। श्रीमती रोली सिंह इससे पूर्व राजस्थान सरकार, कार्मिक विभाग में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थीं।

श्री डी.बी.गुप्ता

13 अक्टूबर 2020 को राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी कर मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री डी.बी.गुप्ता को मुख्यमंत्री राजस्थान इकॉनोमिक ट्रांसफॉर्मेशन सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

डॉ.आलोक त्रिपाठी

13 अक्टूबर 2020 को राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र ने सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर में डॉ.आलोक त्रिपाठी को कुलपति नियुक्त किया है। डॉ.त्रिपाठी पूर्व में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं।

एम.एल.लाठर

14 अक्टूबर 2020 को महानिदेशक (अपराध शाखा) श्री मोहन लाल लाठर ने महानिदेशक पुलिस का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया है।

श्री लाठर ने इस पद पर डॉ.भूपेंद्र सिंह का स्थान लिया है।

डॉ.भूपेन्द्र सिंह

14 अक्टूबर, 2020 को राजस्थान सरकार ने निवर्तमान पुलिस महानिदेशक डॉ.भूपेन्द्र सिंह को राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है।

- डॉ.भूपेन्द्र सिंह ने इस पद पर दीपक उप्रेती का स्थान लिया है।
- इस पद पर उनकी नियुक्ति छह वर्ष या उनके 62 वर्ष आयु पूरी होने तक रहेगी।
- पूर्व DGP डॉ.भूपेन्द्र सिंह ऐसे छठे पुलिस अधिकारी हैं, जो आयोग के चेयरमैन बने हैं।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) में चार सदस्यों की भी नियुक्त
- राज्यपाल कलराज मिश्र ने 14 अक्टूबर, 2020 को एक आदेश जारी कर RPSC में चार सदस्यों की भी नियुक्त की है। इन सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात् आरपीएससी में सदस्यों की संख्या सात हो गई है। आरपीएससी के नियुक्त किए गए सदस्य इस प्रकार हैं:-
 - बाबूलाल कटारा
 - डॉ.संगीता आर्य
 - डॉ.मंजू शर्मा
 - जसवंत राठी

राजस्थान लोक सेवा आयोग

राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष एवं सात सदस्य हैं। यह पद संवैधानिक है एवं राज्य के महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से इन पदों पर नियुक्ति की जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को आयोग सचिवालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है। सचिव द्वारा समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का निष्पादन किया जाता है। सचिव की सहायता के लिए उपसचिव तथा परीक्षा नियन्त्रक होते हैं। रचना आयोग में एक अध्यक्ष एवं सात सदस्य होते हैं।

कार्यकाल आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अधिकतम 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो, के लिए आयोग में कार्यरत रहते हैं।

निरन्जन कुमार आर्य

01 नवम्बर 2020 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री निरन्जन कुमार आर्य ने शासन सचिवालय में राजस्थान के मुख्य सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने राजीव स्वरूप स्थान लिया है।

राजेश यादव

02 नवम्बर 2020 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री राजेश यादव ने शासन सचिवालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव पद का कार्यभार ग्रहण किया।

श्री यादव इससे पूर्व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग में प्रमुख शासन सचिव के पद तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

नवीन महाजन

03 नवम्बर 2020 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री नवीन महाजन ने जलदाय विभाग तथा भू-जल विभाग के शासन सचिव का पदभार ग्रहण किया।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1997 के बैच के अधिकारी श्री महाजन जल संसाधन विभाग, राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग एवं इंदिरा गांधी नहर विभाग के शासन सचिव की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

अरुण सिंह

बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह को बीजेपी राजस्थान का प्रभारी नियुक्त किया गया है।

भारती बेन शियाल

सांसद व पार्टी उपाध्यक्ष भारती बेन शियाल को बीजेपी राजस्थान का सहप्रभारी नियुक्त किया गया है।

दिलीप शिवपुरी

राजस्थान टेनिस संघ के अध्यक्ष पद पर दिलीप शिवपुरी को सर्वसम्मति से चुना गया।

- **डॉ.राजीव शर्मा** - राजस्थान टेनिस संघ के सचिव
- **मोना रामपाल शर्मा** - राजस्थान सॉफ्ट टेनिस संघ अध्यक्ष

श्री डी.बी.गुप्ता

राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राज्य के पूर्व मुख्य सचिव श्री डी.बी.गुप्ता को राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की हैं।

श्री नारायण बारेठ तथा सुश्री शीतल धनकड

राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने श्री नारायण बारेठ तथा सुश्री शीतल धनकड को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की हैं।

मनोहर कांत

राजस्थान सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स तथा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् के अध्यक्ष रह चुके पूर्व आईएस मनोहर कांत को रोलबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है।

- इस पद पर उनका कार्यकाल 2024 तक रहेगा।

अन्य

किरण माहेश्वरी

29 नवंबर 2020 को राजसमंद विधायक व पूर्व मंत्री किरण माहेश्वरी का कोरोना से निधन हो गया। वे नगर निगम चुनाव के दौरान कोटा उत्तर निगम की बीजेपी की प्रभारी थी और यहीं से कोरोना संक्रमित हुई थी। हरियाणा में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।

मास्टर भंवर लाल मेघवाल

16 नवम्बर 2020 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे मास्टर भंवरलाल मेघवाल का मेदांता अस्पताल में उपचार चल रहा था।

अर्जुन प्रजापति

12 नवंबर 2020 को राजस्थान के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री अर्जुन का 64 वर्ष की उम्र में कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। अर्जुन प्रजापति लंबे समय से बीमार थे। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा था।

- अर्जुन प्रजापति को मार्बल, टेराकोटा, ब्रॉन्ज, प्लास्टर ऑफ पेरिस और फाइबर ग्लास से मूर्तियां बनाने में महारथ हासिल थी।
- राजस्थान परंपरागत मूर्ति कला 'बणी-ठणी' को अर्जुन ने नया रूप प्रदान किया। उसके बाद यह कला 'अर्जुन की बणी-ठणी' के नाम से जानी जाने लगी।
- अर्जुन भारत के पहले ऐसे मूर्तिकार थे जो मात्र 20 मिनट में किसी को भी सामने बैठकर उसका क्लोन तैयार कर देते थे। इसके चलते उन्हें 'क्लॉनिंग के महारथी' के खिताब से नवाजा गया।

- अर्जुन ने खेल, कला जगत और सिनेमा से जुड़ी हजारों हस्तियों सहित ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स, मॉरिशस के सर नवीन चन्द्र रामगुलाम, अभिनेत्री मनीषा कोइराला, उद्घोषक पद्मश्री जसदेव सिंह, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पद्मश्री पण्डित विश्वमोहन भट्ट आदि के क्लोन बनाए।
- अर्जुन ने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का क्लोन मात्र 20 मिनट में बनाकर दिखाया तो उन्होंने बदले में 20 मिनट तक माटी से सने अर्जुन के हाथों को अपने हाथों में थामे रखा था। उन्होंने पूछा कि अर्जुन इन उंगलियों में आखिर क्या खास है। बिल क्लिंटन ने अर्जुन को 'मूर्तिकला का जादूगर' का खिताब देकर भी सम्मानित भी किया।
- वर्ष 2004-05 के दौरान अर्जुन प्रजापति ने राजस्थान का पहला मूर्ति शिल्प संग्रहालय 'माटी मानस' का निर्माण करवाया इस आर्ट गैलरी की नींव पूर्व सीएम भैरोंसिंह शेखावत के हाथों रखवाई गई।
- 7 अप्रैल 2010 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने अर्जुन प्रजापति को मूर्तिकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए देश के चौथे नागरिक अलंकरण सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।

जसोदा प्रजापत, वसुंधरा

नीदरलैंड की किड्स राइट संस्था की ओर से दिए जाने वाला अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार- 2020 (International Children's Peace Prize - 2020) के लिए जोधपुर के ओसिया की भैरव सागर निवासी 15 वर्षीय जसोदा प्रजापत तथा टोंक जिले के डारडा तुरकी गाँव रहने वाली वसुंधरा का नाम नामांकित किया गया था। नीदरलैंड की किड्स राइट संस्था द्वारा इस वर्ष 42 देशों के 142 बच्चों को अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।

वसुंधरा

- वसुंधरा, शिव शिक्षा समिति के साथ जीवन कौशल शिक्षा सत्रों के माध्यम से 180 से अधिक लड़कियों को प्रशिक्षित कर चुकी है।
- 'चुप्पी तोड़ो' कार्यक्रम के माध्यम से मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाने में वसुंधरा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- वसुंधरा ने अपने गाँव में बालिकाओं के बीच बाल विवाह और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने में अग्रणी भूमिका निभाई है।

जशोदा

- जशोदा जीवन कौशल शिक्षा की प्रशिक्षक है और उर्मूल ट्रस्ट के साथ मिलकर जीवन कौशल शिक्षा सचिवों के माध्यम से उसने 130 से अधिक लड़कियों को प्रशिक्षित कर चुकी है।
- बाल विवाह की रोकथाम, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और महिला हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठा कर जशोदा अन्य लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभर कर आई हैं।
- जशोदा यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी लड़की किसी भी कारण से शिक्षा से वंचित ना रहे ।

दिवस

08 सितम्बर - अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस

14 सितम्बर - हिन्दी दिवस

16 सितम्बर - विश्व ओज़ोन दिवस

26 सितम्बर - विश्व पर्यटन दिवस

01 अक्टूबर - अन्तर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस

02 अक्टूबर - अहिंसा दिवस

08 अक्टूबर - वायु सेना दिवस

11 अक्टूबर - अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस

15 अक्टूबर - ग्लोबल हैंडवाशिंग डे

21 अक्टूबर - पुलिस शहीद दिवस

31 अक्टूबर - राष्ट्रीय एकता दिवस

लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

20 नवम्बर - विश्व बाल दिवस

20 नवम्बर को यूनिसेफ अपने सहयोगियों के साथ विश्व बाल दिवस के अवसर पर “गो ब्लू” अभियान को बढ़ावा देता है। इसी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विधान सभा भवन पर भी नीले रंग की रोशनी की गयी।

26 नवम्बर - संविधान दिवस

चर्चित स्थान

पत्रिका गेट, जवाहर सर्किल

8 सितम्बर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर बने 'पत्रिका गेट' का लोकार्पण किया।

- इस गेट का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) के मिशन अनुपम के तहत राजस्थान पत्रिका ग्रुप की ओर से किया गया है।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी द्वारा रचित 'संवाद उपनिषद्' और 'अक्षर यात्रा' का भी वर्चुअली विमाचन किया।
- रियासतकालीन ढूंढाइ, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी, बृज, वागड़, गोडवाड व अजमेर से जुड़ी कला संस्कृति जैसे पत्रिका गेट में एक जगह समा गई है। जयपुर की बसावट में जिस तरह 9 अंक का ध्यान रखा गया, इस गेट का निर्माण भी 9 अंक के वास्तु सिद्धांत पर आधारित है। गेट के 9 दरवाजे पर उकेरे गए चित्रों के माध्यम से क्षेत्र विशेष की वास्तुकला और जीवन शैली को दर्शाते हैं। सभी दरवाजों में एक समानता है जो उनकी विशिष्ट पहचान को एक सूत्र में पिरोने का अहसास कराती है।
- जयपुर की बसावट के समय से यहां 7 दरवाजे कृष्णपोल (किशनपोल), चांदपोल, सूरजपोल, गंगापोल, शिवपोल (सांगानेरी गेट), घाटगेट और जोरावर सिंह गेट अस्तित्व में हैं। सवाई मानसिंह ने शहर में आठवां यानी चौड़ा रास्ता का न्यूगेट बनवाया था। इन सभी दरवाजों की अपनी पहचान और अपनी महत्व रहा है। इन्हीं दरवाजों की परिकल्पना के साथ पत्रिका गेट को जयपुर का नौवां दरवाजा बनाया गया है।

पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र, जयपुर

भारत निर्वाचन आयोग का पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र जयपुर में स्थापित किया जायेगा आयोग इस केंद्र से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश में भी जागरूकता कार्यक्रम का संचालन करेगा।

उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा कोरोना रोगियों को चिकित्सालयों की सम्पूर्ण जानकारी देने हेतु वेबसाइट का निर्माण

राज्य सरकार के निर्देशानुसार वैश्विक महामारी घोषित कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों को जल्द से जल्द उचित इलाज उपलब्ध कराने की दृष्टि से उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा एक वेबसाइट का निर्माण किया गया है। जिला कलक्टर श्री चेतन देवड़ा की पहल पर तैयार की गई इस वेबसाइट पर एक क्लिक से ही उदयपुर जिले के उन सभी सरकारी और निजी अस्पतालों की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी जिनमें कोरोना रोगियों के लिए इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। उदयपुर राजस्थान का पहला जिला है जहां पर इस प्रकार की वेबसाइट का निर्माण करते हुए रोगियों को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

वेबसाइट लिंक - sites.google.com/view/covidur/home

वेबसाइट पर उदयपुर के 14 अस्पतालों की जानकारी उपलब्ध होगी

कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों को जल्द से जल्द इलाज उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कोरोना के इलाज की सुविधा से युक्त जिले के सभी 14 चिकित्सालयों का सम्पूर्ण डाटा संकलित किया गया है।

- ईएसआईसी राजकीय चिकित्सालय
- सेटेलाईट हॉस्पिटल सेक्टर 6
- गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल
- पेसिफिक मेडिकल कॉलेज भीलों का बेदला
- पेसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज
- एआईआईएमएस बेडवास
- पारस जेके हॉस्पिटल
- जीबीएच अमेरिकन मधुबन
- शर्मा मल्टीस्पेशलिटी
- चौधरी हॉस्पिटल
- सनराइज हॉस्पिटल
- अरावली हॉस्पिटल
- कल्पना नर्सिंग होम
- जेजे मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल

वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी

वेबसाइट पर सभी चिकित्सालयों के अलग-अलग लिंक दिए गए हैं जिसको क्लिक करने पर लास्ट अपडेशन दिनांक, कोविड पेशेन्ट्स के लिए उपलब्ध कुल बेड, ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीपाइड एवं उपलब्ध बेड की जानकारी के साथ ऑर्डिनरी बेड, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, आईसीयू बेड, बेड पर उपलब्ध वेंटिलेटर की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ ही संबंधित चिकित्सालय का हेल्पडेस्क नंबर, प्रभारी अधिकारी एवं उनके मोबाइल नंबर भी इसमें दर्शाए गए हैं।

इस वेबसाइट पर किसी भी प्रकार की शिकायत करने के लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल के फोन नंबर 181, सभी चिकित्सालयों की बेड उपलब्धता एक्ज़ाई रिपोर्ट, कोरोना में होम आईसोलेशन के लिए गार्डलाईन, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए सरकार से एप्रूव्ड रेड लिस्ट तथा कोविड के बाद के लक्षण और उनके प्रबंधन के बारे में गार्डलाईन भी सम्मिलित की गई है।

गूगल मैप अस्पताल का रास्ता भी दिखाएगा

कोरोना रोगी या परिजन द्वारा चयन किए गए हॉस्पिटल तक पहुंचने में कोई परेशानी न हो इस दृष्टि से वेबसाइट पर सभी अस्पतालों के गूगल मैप लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि इस पर क्लिक करते हुए गूगल मैप के सहारे हॉस्पिटल तक पहुंचा जा सके।

आंगणवा गाँव, जोधपुर

जोधपुर शहर के निकटस्थ गाँव आंगणवा में नवीन आधुनिक कृषि उपज मंडी अनाज शीघ्र स्थापित की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भूमि क्रय हेतु मंडी समिति की ओर से जोधपुर विकास प्राधिकरण को 18.68 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। नवीन मंडी की स्थापना के बाद यहां कृषि जिन्सों की खुली नीलामी से विक्रय, कोल्ड-स्टोरेज, वेयरहाउस और प्रसंस्करण इकाई आदि की स्थापना हो सकेगी।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

10 नवम्बर 2020 को केन्द्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यशोनाइक ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय औषध द्रव्य संग्राहलय का शुभारम्भ किया है।

- संग्राहलय की स्थापना से आयुर्वेदिक औषधियों की गुणवत्ता, क्षमता, संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
- संग्राहलय में गुजरात व राजस्थान क्षेत्र से करीब 500 औषधियों का प्रमाणीकरण तथा मूल्यांकन किया जायेगा।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर

13 नवम्बर, 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर स्थित 'राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान' को मानद विश्वविद्यालय के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया।

- प्रधानमंत्री द्वारा दो आयुर्वेद संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इनमें NIA जयपुर के अतिरिक्त दूसरा संस्थान जामनगर स्थित 'आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान' है।
- NIA, जयपुर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक मान्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है।
- आईटीआरए, जामनगर को संसद के एक अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। यह आयुष क्षेत्र में पहला संस्थान है, जिसके पास INI का दर्जा है।
- NIA जयपुर के पास 14 विभिन्न विभाग हैं तथा यह 54 विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन करता है।
- आयुष मंत्रालय वर्ष 2016 से धन्वंतरि जयंती (धनतेरस) के अवसर पर प्रति वर्ष 'आयुर्वेद दिवस' मनाता है।

प्रधानमंत्री द्वारा पाली में 'स्टैच्यू ऑफ पीस' का अनावरण

16 नवम्बर, 2020 को जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके सम्मान में पाली जिले के जैतपुरा गाँव में स्थित विजय वल्लभ साधना केन्द्र में स्थापित 151 इंच ऊँची प्रतिमा का लोकार्पण किया।

- इस प्रतिमा को 'स्टैच्यू ऑफ पीस' नाम दिया गया है।
- इस प्रतिमा का निर्माण अष्टधातु से किया गया है। इन 8 धातुओं में ताँबा प्रमुख घटक है।
- जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज (1870 -1954) ने अपने सम्पूर्ण जीवन में जैन संत के रूप में निष्ठापूर्वक पूर्ण समर्पण भाव से भगवान महावीर के सन्देश को फैलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

अंगदाता स्मारक, जयपुर

27 नवम्बर, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर के सेंटल पार्क के निकट देश के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन किया गया है।

- यह स्मारक मोहन फाउण्डेशन जयपुर सिटीजन फोरम और नगर निगम जयपुर की ओर से स्थापित एवं संधारित किया गया है।
- इस स्मारक पर वर्ष 2015 से अब तक के अंगदाताओं के नाम उत्कीर्ण किये गए हैं।
- ध्यातव्य है कि एक व्यक्ति के अंगदान से 9 लोगों को नया जीवन मिल सकता है।
- अंगदान करने में तमिलनाडु के बाद राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। भारत में अंगदान करने वालों का प्रतिशत 0.8% है।

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

26 नवम्बर, 2020 को संविधान दिवस के अवसर पर राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र ने उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का ऑनलाइन शिलान्यास किया।

- संविधान पार्क की स्थापना का उद्देश्य देश के युवाओं में संवैधानिक जागरूकता लाना है। संविधान को सरल भाषा में समझाने के लिए 'संविधानजानों अभियान' पूरे देश में सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में चलाया जायेगा।

- 26 नवम्बर, 1949 को भारतीय संविधान निर्माण का कार्य पूर्ण हुआ था इसी क उपलक्ष में वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

- उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के तहत तैयार किए गए मास्टर ऑफ सोशियल वर्क (MSW) कोर्स की शुरुआत की है। ऐसा करने वाला यह प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है।
- नई शिक्षा नीति के अनुसार 6 माह बाद कास छोड़ने पर सर्टिफिकेट दिये जाने की व्यवस्था भी इस कोर्स से शुरू की गई है।

होटल राम बाग पैलेस, जयपुर

अंतर्राष्ट्रीय 'कॉन्डे नास्ट ट्रेवलर रीडर्स च्वाइस अवार्ड्स 2020' की ओर से अक्टूबर, 2020 में जयपुर की राम बाग पैलेस होटल को भारत के टॉप होटल्स में से नंबर-1 तथा विश्व के सर्वश्रेष्ठ होटलों में से 15वीं रैंकिंग दी गई है।

पैलेस ऑन व्हील्स, राजस्थान

राजस्थान की शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया की दूसरी सबसे शाही ट्रेन का खिताब मिला है। एक नामचीन ट्रेवल मैगजीन ने इसे रीडर्स च्वाइस सर्वे व लोकप्रियता के आधार पर रैंकिंग दी है।

मैगजीन ने रीडर्स चॉइस अवार्ड्स 2020 घोषित किए:-

- यूरोप की बेलमंड ब्रिटिश पूलमैन - 96.95 अंक के साथ प्रथम स्थान पर
- पैलेस ऑन व्हील्स - 96.85 अंक के साथ द्वितीय स्थान पर
- महाराजा एक्सप्रेस - 93 अंक के साथ आठवें स्थान पर

अल्ट्रा मेगा रिन्यूअल एनर्जी पावर पार्क, जैसलमेर

केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीप जैसलमेर में अल्ट्रा मेगा रिन्यूअल एनर्जी पावर पार्क' विकसित किया जा रहा है

- राजस्थान में पाकिस्तान के साथ भारत के सीमावर्ती इलाकों में अल्ट्रा मेगा रिन्यूअल एनर्जी पावर पार्क स्थापित करने हेतु राज्य सरकार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम National Thermal Power Corporation (NTPC) और भारतीय सौर ऊर्जा निगम Solar Energy Corporation of India (SECI) से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी।
- यह राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, NTPC और SECI के बीच अलग-अलग जॉइंट वेंचर होगा।
- उल्लेखनीय है की राजस्थान में 1000 किमी. से अधिक लम्बी अंतराष्ट्रीय सीमा है जहाँ वर्तमान में पारम्परिक तरीको से बिजली की आपूर्ति की जाती है। इन सोलर पार्क के जरिए सीमा तक भी निरंतर सौर ऊर्जा पहुँचेगी। इसके लिए जैसलमेर में जमीन चिन्हित की गई है।
- यह पार्क 8000 मेगावाट क्षमता का होगा जिसका विस्तार निम्नानुसार होगा:-
 - पवन ऊर्जा - 4310 मेगावाट
 - सौर ऊर्जा - 3760 मेगावाट
 - बायोमास - 4883 मेगावाट

राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (रील)

- राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (रील) को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से डिजिटली आयोजित कार्यक्रम में '10वाँ PSE एक्सीलेंस अवॉर्ड' प्रदान किया गया है
- भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से देश के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के योगदान को मान्यता देने के लिए इस पुरस्कार की स्थापना की गई है।

पर्यावरण

डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में देश की 1328 वीं तितली

देशभर में तितलियों को गिनने, समझने व संरक्षण की मुहिम को आमजन तक ले जाने के लिए मनाए जा रहे तितली माह यानी “बिग बटरफ्लाई मंथ” के तहत राजस्थान में देश की 1328 वीं तितली की खोज हुई है। स्पीआलिया जेब्रा नामक इस तितली की खोज के सूत्रधार उदयपुर संभाग अंतर्गत डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा कस्बे निवासी तितली विशेषज्ञ व शिक्षक मुकेश पंवार हैं।

पिछले 15 वर्षों से तितलियों पर शोध कर रहे मुकेश पंवार ने इस स्पीआलिया जेब्रा तितली को 8 नवम्बर 2014 को सागवाड़ा के एक फार्म हाउस पर देखा तथा फोटो क्लिक कर इसकी पहचान के लिए उत्तराखंड के भीमताल स्थित बटरफ्लाई शोध संस्थान को भेज दिया। बटरफ्लाई शोध संस्थान ने इस तितली पर करीब 6 साल की लंबी शोध प्रक्रिया के पश्चात् 29 सितम्बर 2020 को इसे भारत की 1328 वीं तितली घोषित किया।

बटरफ्लाई शोध संस्थान के निदेशक पीटर स्मेटाचौक ने बताया कि तेज गति से उड़ान भरने वाली इस तितली की चौड़ाई मात्र 2.5 सेंटीमीटर होती है। इस तितली को वर्ष 1888 में पाकिस्तान के अटौक शहर में देखा गया था।

रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र के बाहरी भाग में दो नई तितलियों की खोज

9 सितंबर को टाड़गर वॉच के फील्ड बायोलोजिस्ट डॉ.धर्मेन्द्र खण्डाल एवं उदयपुर के पर्यावरण वैज्ञानिक डॉ.सतीश शर्मा द्वारा रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र के बाहरी भाग में दक्खन ट्राई कलर पाइड फ्लेट तथा स्पॉटेड स्माल फ्लेट नामक दो नई तितलियों की खोज गई।

उदयपुर में मिली नई प्रजाति की बैबलर चिड़िया

उदयपुर जिले में स्थित फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य के गामड़ा की नाल में एक नई प्रजाति की बैबलर चिड़िया की खोज की गई है। खोजा गया यह एक छोटा रेजीडेंट पक्षी पफ थ्रोटेड बैबलर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पेलोर्नियस रूफीसेप्स है।

इस खोज का श्रेय राजस्थान के ख्यातनाम पर्यावरण वैज्ञानिक और टाइगर वॉच के फील्ड बायोलोजिस्ट डॉ.धर्मेन्द्र खण्डाल, दक्षिण राजस्थान में जैव विविधता संरक्षण के लिए कार्य कर रहे पर्यावरण वैज्ञानिक डॉ. सतीश शर्मा व हरकीरत सिंह संघा को जाता है। इस नई उपलब्धि पर 'इंडियन बर्ड्स' के अंक 16 के भाग 5 में विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की गई है।

पफ थ्रोटेड बैबलर

- यह पक्षी वेबलर वर्ग का सदस्य है।
- इसकी चोंच एवं पैर ललाई लिए हुए हल्के गुलाबी होते हैं। सिर का रंग हल्का चॉकलेटी तथा पीठ का रंग हल्का काला, गला एकदम सफेद तथा छाती पर टूटती गहरी धारियां होती है। आंख के ऊपर सफेद रंग की धारी काली लंबी होकर पीछे गर्दन तक फैली रहती है।
- यह जोड़े या छोटे दलों में रहकर जंगल में नीचे गिरी पड़ी पत्तियों के झुरमुट में भूमि पर पड़े कीड़े-मकौड़े खाती है।
- इस प्रकार की प्रजाति गुजरात के विजयनगर स्थित पोलो फोरेस्ट में मिलती है।
- यह बैबलर प्रजाति भारत के सतपुड़ा बिहार एवं उड़ीसा के पठारी क्षेत्र, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के क्षेत्र, राजमहल पहाड़िया (मध्य पश्चिमी बिहार), केरल के पलक्कड (पालघाट) क्षेत्र, चित्तौरी पहाड़िया आदि क्षेत्रों में पाई जाती है।

प्रवासी पक्षियों की निगरानी के लिए रेस्क्यू सेंटर

- वन विभाग द्वारा नावाँ उपखण्ड मुख्यालय के रतन तालाब तथा सांभर झील पर दूर-दराज से आने वाले पक्षियों की निगरानी के लिए रेस्क्यू सेंटर स्थापित किये गए हैं।
- गत वर्ष सांभर झील में बोटुलिज़्म नामक बीमारी से हजारों की संख्या में पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। इस कारण विभाग ने यह रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है।

डेजर्ट नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्त प्रायः पक्षी लेपविंग दिखा

डेजर्ट नेशनल पार्क के घास के मैदान में लेपविंग की गंभीर रूप से लुप्त प्रायः प्रजातियों को देखा गया है। स्थानीय पक्षी गाइड मूसा खान ने दुर्लभ पक्षी को पहली बार देखा था। उन्होंने बताया कि इस पक्षी को डीएनपी के बाहरी इलाके में देखा था, जिस पर स्थानीय बर्डवॉचर्स को सूचित किया। बहुत तेजी से अपनी संख्या में गिरावट और आवास स्थलों का नुकसान झेलने के कारण यह पक्षी लुप्त प्रायः ही माना जाता यह पक्षी कॉरसर के झुंड के साथ देखा गया था।

सरकारी परियोजनायें

वात्सल्य व समर्थ योजना

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 14 से 20 नवम्बर तक आयोजित किए जाने वाले बाल अधिकार सप्ताह का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया।

- वर्चुअल कार्यक्रम 'बाल संगम' में श्री गहलोत ने 'वात्सल्य योजना' एवं 'समर्थ योजना' के दिशा-निर्देशों की पुस्तिका का विमोचन भी किया।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यक्रम के दौरान वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में की गई नेहरू बाल संरक्षण कोष की स्थापना सम्बन्धी घोषणा की अनुपालना में अनाथ एवं बेसहारा बच्चों के लिए 'वात्सल्य योजना' एवं 'समर्थ योजना' का शुभारम्भ किया।
- मुख्यमंत्री ने जोधपुर में ICICI बैंक के सहयोग से राजकीय बाल संरक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों के लिए कौशल विकास और परामर्श केन्द्र का भी शुभारम्भ किया। यह परामर्श केन्द्र बैंक के साथ मिलकर कार्य करेगा और बाल संरक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों को प्रशिक्षण एवं परामर्श प्रदान करेगा।

राजस्थान समर्थ योजना

- 18 वर्ष की आयु पूरी कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने वाले बच्चों के लिए समर्थ योजना शुरू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।
- इस योजना के तहत उन सभी बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा जो अनाथालयों में रहते हैं। संस्थागत देख-रेख से बाहर निकलने वाले बच्चों को व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण के साथ ऋण एवं परामर्श सेवाएँ भी उपलब्ध कराई जाएँगी।
- बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें उन्हें बेसिक कंप्यूटर के साथ-साथ मोबाइल रिपेयरिंग जैसे अन्य दूसरे तकनीकी कौशल को सिखाया जाएगा। इस प्रकार बच्चे अपनी रुचि के अनुसार किसी भी एक टेक्निकल कोर्स को कर सकते हैं।

राजस्थान वात्सल्य योजना

- वात्सल्य योजना के अंतर्गत बाल देख-रेख संस्थाओं में रह रहे बच्चों को वैकल्पिक परिवार आधारित देख-रेख सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। बच्चे का पालन पोषण एवं देखभाल करने वाले माता-पिता को एक निश्चित अवधि के लिए प्रतिमाह 2 हजार रु की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य में रहने वाले सभी गरीब और बेसहारा अनाथ बच्चों का पालन पोषण ठीक प्रकार से हो सके।

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना

19 नवम्बर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 103वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 'इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना' (Maternity nutrition scheme) का शुभारम्भ किया। इस योजना की शुरुआत महिला सशक्तीकरण की दिशा में राजस्थान सरकार द्वारा उठाया गया एक अहम कदम है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। गर्भवती महिलाओं को 5 किशतों में 6 हजार रुपए दिए जाएंगे।

योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है:-

- राज्य सरकार द्वारा यह योजना पूरे प्रदेश में चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी।
- इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं तथा तीन वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना है।
- योजना के अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी महिलाओं को पांच चरणों में 6 हजार रुपए की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।
- पहले चरण में यह योजना प्रदेश के 4 अत्यधिक पिछड़े आदिवासी जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में शुरू की गई है।
- योजना में महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा खान एवं भूविज्ञान विभाग मिलकर कार्य करेंगे। प्रतिवर्ष करीब 77 हजार से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ANM एवं आशा सहयोगिनी लाभार्थी महिलाओं को उचित पोषण एवं शिशु की देखभाल के संबंध में परामर्श देंगी। चिल्ड्रन्स इन्वेस्टमेंट फण्ड फाउण्डेशन तथा आईपीई ग्लोबल, योजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकार का सहयोग करेंगे।
- योजना के तहत 1 नवम्बर 2020 एवं इसके बाद जन्मे दूसरे बच्चे के समय गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा।
- इस योजना पर सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि निम्न चरणों में दी जाएगी:-

किश्त	सहायता राशि	चरण
पहली किश्त	1000 रु	गर्भावस्था जांच व पंजीकरण होने पर
दूसरी किश्त	1000 रु	दो प्रसव पूर्व जांचें पूरी होने पर
तीसरी किश्त	1000 रु	संस्थागत प्रसव होने पर
चौथी किश्त	2000 रु	बच्चे के जन्म के 105 दिन तक सभी नियमित टीके लगने तथा बच्चे का जन्म पंजीकरण होने पर
पांचवी (अंतिम) किश्त	1000 रु	दूसरी संतान पैदा होने के तीन माह के भीतर परिवार नियोजन के साधन अपनाने पर

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान

त्योहारों के समय में चलाया जाने वाला 'शुद्ध के लिए युद्ध अभियान' अब वर्षभर जारी रहेगा।

- अभियान के तहत वर्षभर लगातार मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देश में पहली बार राजस्थान ने मिलावट पर सही जानकारी देने की सूचना देने वाले को 51 हजार का पुरस्कार दिया जायेगा।
- अभियान में 'निरोगी राजस्थान' के तहत नियुक्त किए गए स्वास्थ्य मित्र की सहायता ली जाएगी।

खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ

- राजस्थान में देश की सबसे ज्यादा 11 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ जयपुर, जोधपुर, अलवर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, बीकानेर और बाँसवाड़ा में हैं चूरू और जालौर में भी जल्द ही ये प्रयोगशालाएँ शुरू होने वाली हैं।
- इसके अतिरिक्त, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर में मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ भी उपस्थित हैं।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में दण्ड का प्रावधान

- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के नियमों और विनियमों के अनुसार, धारा 51 के तहत किसी भी खाद्य पदार्थ को घटिया पाए जाने पर अधिकतम 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है, जबकि धारा 52 के तहत, मिसब्रॉडेड के मामलों में अधिकतम 3.50 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है।
- असुरक्षित के मामलों में छह महीने तक कारावास और अधिनियम की धारा 59 के तहत 10 लाख तक का जुर्माना है और यह मामले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए जाते हैं।

एक जिला एक उत्पाद योजना

राजस्थान सरकार ने इस साल की शुरुआत (फरवरी-मार्च) में हर जिले की पहचान रहे उत्पादों को चिह्नित कर इन पर विशेष फोकस करने की योजना बनाई है। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा और तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल ने संभागवार हर जिले की खासियत रहे उत्पादों को लेकर उद्यमियों और सरकारी अधिकारियों से संवाद कर योजना पर काम शुरू कर दिया है। खासकर सूक्ष्म और लघु उद्योगों में निर्मित ऐसे उत्पादों और सेक्टरों को ध्यान में रख कर चिह्नित किया गया, जिन्हें बेहतर संभावनाओं के साथ बड़े प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है।

जिलेवार चुने गए उत्पाद व सेक्टर निम्न हैं:-

क्र. सं.	जिला	उत्पाद
01.	अलवर	खाद्य प्रसंस्करण व हस्तशिल्प
02.	अजमेर	गोटालूम व हस्तशिल्प
03.	बांसवाड़ा	हस्तशिल्प व कृषि उद्योग
04.	बारां	कृषि उद्योग, हस्तशिल्प, हथकरघा और वनोत्पाद
05.	बाड़मेर	हस्तशिल्प व हथकरघा
06.	भरतपुर	खाद्य प्रसंस्करण
07.	भीलवाड़ा	वस्त्र व खनिज
08.	बीकानेर	खाद्य प्रसंस्करण व ऊनी वस्त्र
09.	बूंदी	खाद्य प्रसंस्करण व चावल
10.	चित्तौड़गढ़	स्टोन कटिंग व होटल पर्यटन
11.	चूरू	लकड़ी हस्तशिल्प
12.	दौसा	खाद्य प्रसंस्करण व हस्तशिल्प
13.	धौलपुर	दुग्ध
14.	झुंजरपुर	हस्तशिल्प व स्टोन
15.	हनुमानगढ़	कृषि उद्योग
16.	जयपुर	इंजीनियरिंग उत्पाद, कास्टिंग व इलेक्ट्रिकल उत्पाद
17.	जालौर	हथकरघा
18.	जैसलमेर	स्टोन

19.	झालावाड़	स्टोन व हथकरघा
20.	झुंझुनूं	कृषि व खाद्य प्रसंस्करण
21.	जोधपुर	हस्तशिल्प
22.	करौली	स्टोन व लाख चूड़ी
23.	कोटा	खाद्य प्रसंस्करण
24.	नागौर	हस्तशिल्प व औजार
25.	पाली	वस्त्र, पर्यटन
26.	प्रतापगढ़	कृषि, खाद्य प्रसंस्करण
27.	राजसमंद	स्टोन कटिंग, सिरेमिक, ज्वैलरी व हस्तकला
28.	सवाई माधोपुर	पर्यटन व खाद्य प्रसंस्करण
29.	सीकर	हस्तशिल्प व खनिज
30.	सिरोही	मार्बल हस्तशिल्प
31.	श्रीगंगानगर	कृषि प्रसंस्करण
32.	टोंक	स्टोन व कृषि प्रसंस्करण
33.	उदयपुर	वस्त्र, हस्तशिल्प व पर्यटन

सामान्य करंट अफेयर्स

उद्योग विभाग व सिडबी के बीच करार संपन्न

11 सितंबर 2020 को राजस्थान के एमएसएमई (MSME) उद्यमों को वित्तीय, तकनीकी, विपणन, निर्यात और अन्य सहयोग व समन्वय के लिए उद्योग विभाग व सिडबी साथ मिलकर काम करेंगे। इस संबंध में उद्योग विभाग की ओर से आयुक्त श्रीमती अर्चना सिंह और सिडबी की ओर से महाप्रबंधक श्री बलबीर सिंह द्वारा करार पर हस्ताक्षर किए गए।

मोक्ष कलश योजना-2020 को प्रशासनिक मंजूरी

22 सितम्बर 2020 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 'मोक्ष कलश योजना-2020' को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इस योजना में नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम होगा जबकि वित्त पोषक विभाग देवस्थान विभाग होगा।

- इस योजना के अंतर्गत अपनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने हेतु परिवार के दो सदस्य अस्थि कलश के साथ हरिद्वार आने-जाने के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं।
- योजना के तहत हुए समस्त व्यय के भुगतान की व्यवस्था देवस्थान विभाग द्वारा की जाएगी।
- आयकरदाता एवं सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा। योजना के तहत पंजीयन के समय मृत व्यक्ति के बारे में पूरा विवरण देना होगा।

'वस्त्र 2020' वर्चुअल एक्सपो

22 सितंबर 2020 को उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टेक्सटाइल एंड अपैरल फेयर के 7वें संस्करण का वर्चुअल एक्सपो, 'वस्त्र-2020' का उद्घाटन किया।

- वर्तमान परिदृश्य के कारण, जब यात्रा और व्यक्तिगत कनेक्टिविटी सीमित है, फेयर पहली बार वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया। यह मेगा-इवेंट 22 से 27 सितंबर तक आयोजित किया गया।
- यह टेक्सटाइल फेयर रीको (RIICO) और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है।
- 'वस्त्र-2020' पूर्ण रूप से बी-2-बी फेयर था। प्रदर्शनी के सभी पांच दिनों में प्री-फिक्स्ड बी-2-बी मीटिंग्स के साथ-साथ ऑन द स्पॉट मीटिंग्स भी आयोजित की गईं।

"टीएडी सुपर-30" प्रोजेक्ट

जनजाति एवं सहरिया समुदाय के विद्यार्थियों के प्रशासनिक सेवाओं में चयन का मार्ग प्रशस्त करने हेतु "टीएडी सुपर-30" प्रोजेक्ट के तहत प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से निःशुल्क ऑन-लाइन प्री कोचिंग उपलब्ध करवाई जायेगी।

प्रोजेक्ट के तहत 20 छात्र एवं 10 छात्राओं को राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए आरएस ऑन-लाइन प्री कोचिंग दी जायेगी। तैयारी के इच्छुक ऐसे अभ्यर्थियों को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करना आवश्यक होगा। ऐसे अभ्यर्थियों का चयन विभाग द्वारा गठित एक कमेटी द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थियों का चयन 80 प्रतिशत शैक्षणिक योग्यता के अंक एवं प्रतिशत साक्षात्कार के अंक अनुसार चयनित होने पर मेरिट के आधार पर किया जायेगा।

राज्यपाल ने वेद विद्यापीठ के डिजिटल प्लेटफार्म का लोकार्पण किया

26 अक्टूबर 2020 को राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज मिश्र ने राजभवन से बांसवाड़ा स्थित गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में वेद विद्यापीठ के डिजिटल प्लेटफार्म का लोकार्पण किया।

- श्री कलराज मिश्र ने कहा कि पूरे भारत में अकेले बांसवाड़ा में ही ऋग्वेद की शांख्यान शाखा की ऋचाओं के सस्वर गान करने वाले ज्ञाता हैं, वेद विद्यापीठ की स्थापना से उनके संरक्षण और सामवेद मंत्रों की गायन परम्परा को सहेजे जाने का महत्वपूर्ण कार्य हो सकेगा।
- उन्होंने वेद विद्यापीठ के जरिए प्राचीन भारतीय ज्ञान को वैज्ञानिक रूप में सहेजे जाने पर जोर दिया साथ ही भारतीय संस्कृति की इस अनुपम धरोहर को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया।
- इस अवसर पर राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री मिश्र ने वेद विद्यापीठ की विद्वत चर्चा श्रृंखला 'सारस्वत' के शुभारम्भ की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि वेद विज्ञान से जुड़े विविध आयामों पर होने वाली चर्चा का जनहित में सार्वजनिकरण करने के भी प्रयास किए जाएं।

'हम राजस्थानी' कार्यक्रम

7 अक्टूबर 2020 को राजस्थान फाउण्डेशन के अध्यक्ष श्री धीरज श्रीवास्तव तथा सिम्पली जयपुर की सम्पादक श्रीमती अंशुहर्ष के मध्य एक MOU हस्ताक्षर किया गया। इसके अंतर्गत राजस्थान फाउण्डेशन द्वारा देश-विदेश में बसे राजस्थान की विभूतियों को 'हम राजस्थानी' कार्यक्रम के माध्यम से सोशल मीडिया पर प्रकाश में लाया जाएगा।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश-विदेश में बसे ऐसे राजस्थानी सपूतों से परिचय कराना है जिन्होंने अपनी बुद्धि कौशल और मेहनत से सफलता के नये आयाम स्थापित किये हैं। जिससे युवा पीढ़ी प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्राप्त करेगी। इसकी पहली कड़ी में मुम्बई में बसे राजस्थानी जनरल आलोकराज के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से रूबरू करवाया जायेगा।

राजस्थान तिलम संघ की राजफैड में विलय की प्रक्रिया शुरू होगी

राजस्थान सरकार द्वारा सहकारिता के ढांचे को मजबूत करने के लिए तिलम संघ का राजफैड में विलय की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

- तिलम संघ वर्तमान में लगभग 167 करोड़ रुपये के घाटे में है तथा लगभग 151 करोड़ रुपये की देनदारिया है।
- सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना अनुसार वर्ष 1991 से पहले तिलम संघ राजफैड का ही अंग था लेकिन विश्व बैंक की शर्तों के आधार पर 1991 में राजफैड से अलग कर तिलम संघ की स्थापना की गई थी तथा वर्ष 2008 से तिलम संघ के तीनों उत्पादन संयंत्र (कोटा, श्रीगंगानगर एवं फतेहनगर) बंद है।सहकारिता मंत्री के अनुसार तिलम संघ के राजफैड में विलय से राजफैड को भी लाभ होगा।

F.M.D. टीकाकरण अभियान

12 अक्टूबर 2020 से गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं को खुरपका-मुहँपका बीमारी से बचाने के लिये राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम National Animal Disease Control Programme (NADCP) के तहत प्रदेशव्यापी खुरपका-मुहँपका रोग टीकाकरण (Foot & Mouth Disease FMD) अभियान प्रारम्भ किया गया हैं।

- FMD से देश अनुमानत लगभग 20 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक हानि होती है ओर दूध का उत्पादन लगभग 50 प्रतिशत तक कम हो जाता है।
- FMD वैक्सीनेशन अभियान के प्रथम चरण में 12 अक्टूबर से राज्य के 18 जिलों के समस्त गोवंश एवं भैंसवंश में 149 लाख पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा तथा 4 से 5 माह की उम्र के बछड़े-बछड़ियों को प्रारम्भिक वैक्सीन के एक माह पश्चात 24 लाख पशुओं का बूस्टर वैक्सीनेशन सहित कुल 173.33 पशुओं का टीकाकरण व टैगिंग का कार्य किया जाएगा।
- FMD टीकाकरण हेतु विगत 05 वर्षों से टीकाकरण कार्यक्रम सम्पादित किया जा रहा है परन्तु इस वर्ष से प्रारंभ किया जाने वाला टीकाकरण अत्यंत विशिष्ट है क्योंकि इसके अन्तर्गत टीकाकरण किये जाने वाले प्रत्येक पशु के कान में 12 नम्बर का यूनिक आई.डी.-बार कोड युक्त टैग लगाया जावेगा तथा पशु-पशुपालक एवं टीकाकरण की समस्त सूचनाओं को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) द्वारा विकसित किये गये सॉफ्टवेयर इनाॅफ (INFORMATION NETWORK FOR ANIMAL PRODUCTIVITY & HEALTH : INAPH) पर इन्द्राज किया जायेगा।

खुरपका- मुहँपका रोग (Foot & Mouth Disease FMD)

यह विभक्त-खुर वाले पशुओं का अत्यन्त संक्रामक एवं घातक विषाणुजनित रोग है। यह गाय, भैंस, भेंड़, बकरी, सूअर आदि पालतू पशुओं एवं हिरन आदि जंगली पशुओं को होता है।

FMD लक्षण:-

- पशु को तेज बुखार, मुंह, मसूड़े, जीभ के ऊपर नीचे होंठ के अन्दर का भाग खुरों के बीच की जगह पर छोटे-छोटे दाने उभर आते हैं, फिर धीरे-धीरे ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। तथा फट कर उनमें जख्म हो जाता है।
- पशु कमजोर होकर सुस्त पड़ जाते हैं तथा दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है।

अभियान 'आवाज' (Action Against Women related crime and Awareness for Justice)

13 अक्टूबर 2020 से राज्य में महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें अपने अधिकारों एवं कानूनों के प्रति सजग करने तथा लैंगिक समानता की भावना प्रबल करने के साथ ही महिला अपराधों में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा विशेष अभियान 'आवाज' (Action Against Women related crime and Awareness for Justice) प्रारम्भ किया गया है।

अभियान के तहत प्रथम माह (13.10.2020 से 12.11.2020 तक) में महिला अत्याचार व बलात्कार की घटनाओं को रोकने के साथ ही महिलाओं में सुरक्षा सम्बन्धी कानूनी जागरूकता एवं युवाओं को नारी सम्मान के महत्व को समझाने हेतु विशेष प्रयास किये जाएंगे।

'अपनी बात' का आयोजन

- अभियान 'आवाज' के तहत प्रत्येक पंचायत स्तर पर महिला अत्याचार व बलात्कार सम्बन्धी कानून के विषय में जागरूकता एवं इनके दुष्परिणामों के बारे में आमजन को अवगत करवाने हेतु सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक जिला कलेक्टर से समन्वय स्थापित कर 'अपनी बात' बैठक का आयोजन किया जायेगा।

- जिलों में पदस्थापित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रधिकार में माह में कम से कम चार बार महिला सुरक्षा सम्बन्धी थाना स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय 'अपनी बात' कार्यक्रमों में भाग लेकर आमजन को जागरूक करेंगे।

पहला राजस्व दिवस समारोह

15 अक्टूबर 2020 को राजस्व विभाग ने राज्य में पहला राजस्व दिवस मनाया।

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समारोह को संबोधित करते हुए राजस्व विभाग की अपना खाता, ई-गिरदावरी, कृषि ऋण रहन पोर्टल, ई-पंजीयन आदि सेवाओं का ई-लोकार्पण किया।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राजस्थान राजस्व बोर्ड की पत्रिका 'राविरा' का विमोचन भी किया।

राजस्व दिवस

15 अक्टूबर 1955 को प्रदेश में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हुआ था खेत जोतने वाले काश्तकारों को खातेदारी अधिकार प्रदान कर भू-स्वामी घोषित किया गया था। इसलिए इस दिन को राजस्व दिवस के रूप में मनाया जाता है।

“शुद्ध के लिए युद्ध” के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कोर ग्रुप का गठन

मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप ने प्रदेश भर में 26 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन, सुचारू संचालन, प्रबंधन और प्रबोधन के लिए एक कोर ग्रुप का गठन किया है। इस कोर ग्रुप में गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के शासन सचिव शामिल होंगे, जबकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग समन्वयक की भूमिका निभाएगा। चिकित्सा विभाग ही इस ग्रुप का प्रशासनिक विभाग भी होगा।

अभियान के अंतर्गत दूध, मावा, पनीर, दूध उत्पाद, आटा, बेसन, खाद्य तेल एवं घी, सूखे मेवे, मसालों की जांच की जाएगी। अभियान की अवधि में एडल्टरेशन, अनसेफ में संलिप्त उत्पादक के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सूचना देने वाले को सूचना सही पाए जाने पर 51 हजार की राशि दी जाएगी।

14 जिलो में नये प्रभारी सचिव बनाये गये

1 अक्टूबर 2020 को राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी कर 13 जिलों में नये प्रभारी सचिव बनाये गए हैं।

क्र.सं.	जिला	प्रभारी सचिव	पद
1	उदयपुर	श्री अजिताभ शर्मा	खान एवं पेट्रोलियम विभाग प्रमुख सचिव
2	भीलवाड़ा	डॉ.आरूषी मलिक	संभागीय आयुक्त अजमेर
3	भरतपुर	श्री आनन्द कुमार	प्रमुख शासन सचिव राजस्व
4	सवाई माधोपुर	श्री प्रेमचन्द बेरवाल	भरतपुर के संभागीय आयुक्त
5	बीकानेर	श्री आलोक गुप्ता	पर्यटन एवं देवस्थान विभाग प्रमुख
6	श्रीगंगानगर	श्री भंवर लाल मेहरा	संभागीय आयुक्त बीकानेर
7	हनुमानगढ़	श्रीमती अरूणा राजोरिया	स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स ऐजेंसी की चीफ एक्जिकेटिव
8	पाली	डॉ.समित शर्मा	जोधपुर के संभागीय आयुक्त
9	कोटा	श्री राजेश यादव	जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भू-जल विभाग के प्रमुख शासन सचिव
10	झालावाड़	श्री कैलाश चंद मीणा	कोटा के संभागीय आयुक्त
11	जयपुर	श्री भास्कर ए सावंत	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव
12	अलवर	श्री सोमनाथ मिश्र	संभागीय आयुक्त, जयपुर
13	बांसवाड़ा	श्री एन.एल मीणा	गृह सचिव
14	सिरोही	श्री पूरण चन्द्र किशन	आयुक्त ई. जी. एस. एवं निदेशक सेनिटेशन पंचायतीराज एवं स्वायत्त शासन विभाग

‘म्हारी योजना म्हारो अधिकार’ ऑन लाईन विधिक सेवा शिविर का शुभारम्भ

8 अक्टूबर 2020 को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन को विधिक सेवा व सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘म्हारी योजना म्हारो अधिकार’ ऑनलाइन विधिक सेवा शिविर का शुभारम्भ किया गया।

- शिविर का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के चलते आम जनता में विधियों एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने व उनकी विधिक आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान करना है।
- प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष व न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय श्री संगीत लोढ़ा ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में एक-एक चयनित पंचायत समिति में इस विधिक सेवा का आयोजन किया जा रहा है।

देश की पहली सरकारी मानसिक स्वास्थ्य टोल फ्री सेवा ‘मन-संवाद’ का शुभारंभ

10 अक्टूबर 2020 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ.रघु शर्मा द्वारा देश की प्रथम सरकारी मानसिक स्वास्थ्य टोल फ्री हेल्पलाइन ‘मन-संवाद’ (1800-180-0018) का शुभारंभ किया गया। इस हेल्पलाइन के जरिए निःशुल्क टेली काउंसलिंग की सुविधा मानसिक रोगियों को प्रदान की जाएगी।

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर ‘जागरूकता पोस्टर’ का विमोचन

चिकित्सा मंत्री द्वारा विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर ‘जागरूकता पोस्टर’ का भी विमोचन किया गया।

- **विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2020 थीम** - मानसिक सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करना और सबको इलाज उपलब्ध कराना

मैमोरी क्लीनिक का शुभारंभ

चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मैमोरी क्लीनिक का शुभारंभ किया। इस क्लीनिक के जरिए सभी उम्र के मरीजों की याद्दाश्त संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाएगा। यह क्लीनिक मनोरोग चिकित्सा संस्थान, जयपुर में संचालित होगा।

अलवर जिले की उपतहसील टहला तहसील में क्रमोन्नत तथा तहसील राजगढ़ का हुआ पुनर्गठन

15 अक्टूबर 2020 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर अलवर जिले की तहसील राजगढ़ का पुनर्गठन करते हुए उपतहसील टहला को तहसील में क्रमोन्नत किया गया है।

- अधिसूचना के अनुसार क्रमोन्नत तहसील टहला के कार्यक्षेत्र में 4 भू- अभिलेख निरीक्षक वृत्त टहला, खोह, गोलाकाबास तथा तालाब को सम्मिलित किया गया है, जिनमें कुल 16 पटवार मण्डल शामिल हैं। इन पटवार मण्डलों का कुल क्षेत्रफल 31 हजार 900.71 हैक्टेयर है।
- इसी प्रकार पुनर्गठित तहसील राजगढ़ के कार्यक्षेत्र में 5 भू- अभिलेख निरीक्षक वृत्त राजगढ़, नीमला, राजपुरबड़ा, थाना तथा ढिगावड़ा को सम्मिलित किया गया है, जिनमें कुल 19 पटवार मण्डल शामिल हैं। इन पटवार मण्डलों का कुल क्षेत्रफल 24 हजार 95.31 हैक्टेयर है।
- राज्य सरकार द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 15 एवं 16 के प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलवर जिले की तहसील राजगढ़ का पुनर्गठन तथा उपतहसील टहला को तहसील में क्रमोन्नत किया गया है।

देश-विदेश में बसे राजस्थान के डॉक्टर्स को अपनी माटी से जोड़ने के लिए 'डोरी' का गठन

16 अक्टूबर 2020 को राजस्थान फाउंडेशन द्वारा "डोरी" DORI (डॉक्टर ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल) का गठन किया है जिसके सदस्य राजस्थान मूल के वे डॉक्टर हैं जो विदेशों में रह रहे हैं। इन सभी डॉक्टरों को अपनी जमीन से जोड़ने के लिए राजस्थान फाउंडेशन मुख्य भूमिका निभा रहा है। कोरोना के समय में मेडिकल कनेक्टिविटी बढ़ाने और इन सभी डॉक्टर्स का संपर्क राजस्थान से बनाये रखने हेतु साप्ताहिक रूप से उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़े सवालों के साथ ओपन फोरम भी रखा जाता है जिसमें जुड़ कर लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं।

29 खिलाड़ियों को राजकीय सेवा में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति

25 अक्टूबर 2020 को प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने खेल पदक विजेता 29 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न आधार पर राजकीय सेवा में नियुक्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही प्रदेश के खिलाड़ियों को दोगुना दैनिक भत्ता देने का निर्णय लिया है।

- प्रस्ताव के अनुसार, प्रवर्ग 'क' के 11 खिलाड़ियों को राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान आबकारी सेवा, राजस्थान वन सेवा, राजस्थान शिक्षा विभाग एवं तकनीकी अभियांत्रिकी सेवा में नियुक्ति दी जाएगी। इनमें से 6 खिलाड़ियों को उप अधीक्षक पुलिस एवं 5 खिलाड़ियों को सहायक वन संरक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी।
- इसी प्रकार, प्रवर्ग 'ख' में 11 खिलाड़ियों पुलिस उप निरीक्षक, एक खिलाड़ी को आबकारी रक्षक, पांच खिलाड़ियों को क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा एक खिलाड़ी को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक-द्वितीय के पद पर नियुक्ति दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को वर्तमान में मिलने वाले दैनिक भत्ते को भी दोगुना करने का महत्वपूर्ण निर्णय किया है। अब राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रतिदिन 500 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 300 रुपये के स्थान पर 600 रुपये मिलेंगे।

राज्य विधानसभा में राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 सहित अनेक विधेयक पारित

2 नवम्बर 2020 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक को चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कोविड -19 एक ऐसा संक्रामक रोग है जो पूरे देश में तेजी से पैर पसार रहा है। महामारी को विनियमित कर इसकी प्रभावी रोकथाम हेतु राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 अधिनियमित किया था जिसकी धारा 4 यह उपबंधित करती है कि राज्य सरकार ऐसे अस्थायी विनियम या आदेश विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनका पालन महामारी के फैलाव को रोकने के लिए जनता द्वारा किया जाना है।

समूचे विश्व के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय के अनुसार मास्क ही इस महामारी के फैलाव को नियंत्रित कर लाखों का जीवन बचा सकता है। इसी विचार से लोक स्थान, लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यस्थल या किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, आम समारोह या जमाव में मास्क पहनना अनिवार्य किया जाना चाहिए और ऐसे स्थानों पर ऐसे व्यक्तियों के आवागमन को प्रतिषिद्ध किये जाने का विनिश्चय किया है, जिन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है। इसीलिए राजस्थान महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020, को ध्वनिमत से पारित किया गया।

31 अक्टूबर 2020 को बुलाये गए राजस्थान विधानसभा के 5वें सत्र में उपर्युक्त विधेयक के अतिरिक्त कई अन्य विधेयक भी पारित हुए जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-

- सिविल प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020
- आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020
- कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020
- कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020

केन्द्र के कृषि कानूनों के विरोध में राजस्थान विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित

राजस्थान सरकार ने 2 नवम्बर, 2020 को केन्द्र द्वारा हाल ही में पारित कृषि कानूनों के विरुद्ध तीन संशोधन विधेयकों को पारित किया है। राजस्थान राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए तीन संशोधन विधेयक निम्न हैं:-

- कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020
- कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020
- आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक 2020

राज्य विधानसभा में पारित इन संशोधन विधेयकों का उद्देश्य केन्द्र सरकार द्वारा पारित कृषि सम्बन्धी तीन कानूनों के प्रभाव को राज्य के किसानों पर निष्प्रभावी बनाना है।

राज्य सरकार ने इन विधेयकों में मोटे तौर पर यह प्रावधान किया है कि किसी कम्पनी या व्यक्ति द्वारा किसानों के साथ उनकी उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम दर पर खरीदने का कोई समझौता वैध नहीं होगा। इनमें किसानों के उत्पीड़न पर कम से कम तीन वर्ष की कैद व 5 लाख रु तक जुर्माना शामिल है।

केन्द्र सरकार द्वारा सितम्बर 2020 में पारित विधेयक जिनके खिलाफ उक्त संशोधन विधेयक पारित हुए

- किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020
- 'कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020
- आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राजस्थान को देश में सामुदायिक शौचालय निर्माण में मिला तृतीय पुरस्कार

- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राजस्थान को देश में सामुदायिक शौचालय निर्माण में तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से यह पुरस्कार राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने ग्रहण किया।

- राज्य को यह पुरस्कार गरीब कल्याण रोजगार योजना के अंतर्गत लॉकडाउन के दरम्यान वापस आए प्रवासी राजस्थानियों के लिए रोजगार एवं स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए योजना के अंतर्गत 5,537 के लक्ष्यों के विरुद्ध 70 प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने में सफल रहने के कारण संपूर्ण भारतवर्ष में तृतीय स्थान प्राप्त किया गया है।

'राष्ट्रीय जल पुरस्कार- 2019' सामान्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य में राजस्थान का तीसरा स्थान

जल संसाधनों के प्रबन्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2019' के तहत सामान्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में तीसरा पुरस्कार प्रदान किया गया है।

- केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू के मुख्य आतिथ्य में आयोजित ऑनलाइन समारोह में राजस्थान की ओर से जल संसाधन विभाग के शासन सचिव नवीन महाजन ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।
- जल संसाधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए गत करीब 15 माह की अवधि में राजस्थान ने यह 7वाँ बड़ा पुरस्कार प्राप्त किया है।
- केन्द्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से प्रतिवर्ष देशभर में जल संसाधन प्रबन्धन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए और हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिए जाते हैं।

राजस्थान देश का पहला राज्य है जहाँ स्थानीय निकायों में निःशक्तों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा।

प्रदेश के स्थानीय निकायों में भी अब निःशक्तों की सीधी भागीदारी हो सकेगी। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। हाल ही में सम्पन्न नगरीय निकायों में एक महिला व एक पुरुष (प्रति निकाय) निःशक्त मनोनीत होगा।

नई शिक्षा नीति 2020 के अंतिम प्रारूप के नए नियम

1-12वीं तक के विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के अंतिम प्रारूप में निम्न बातों का समावेश कर राज्यों को अनिवार्य पालना हेतु भेजा है:-

- कक्षा 1 से 12 के छात्रों को महीने में 10 दिन बस्ता स्कूल नहीं लाना होगा।
- इन 10 दिनों में कक्षा 6 से 8वीं के बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग कराई जायेगी।
- पहली व दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों को क्लास वर्क के लिए एक नोटबुक तथा तीसरी से पांचवी कक्षा के विद्यार्थियों को दो नोटबुक रखनी होगी।
- छठी से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को क्लास वर्क के लिए खुली फाइल में कागज रखने होंगे।
- पहली से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का बस्ता विद्यार्थी के वजन का 10 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- स्कूल में बस्ते का वजन जाँचने के लिए डिजिटल मशीन लगाना अनिवार्य होगा।
- स्कूलों को बस्ते का बोझ कम करने के लिए मिड-डे मील, पेयजल और बुक बैंक की व्यवस्था करनी होगी।

कक्षावार बस्ते का वजन निम्नानुसार होगा:-

क्र. सं.	कक्षा	बस्ते का वजन
1.	प्री-प्राइमरी	बस्ता नहीं होगा
2.	1 - 2री	1.6 - 2.2 किलो
3.	3 - 5वीं	1.7 - 2.5 किलो
4.	6 - 7वीं	2 - 3 किलो
5.	8वीं	2.5 - 4 किलो
6.	9 - 10वीं	2.5 - 4.5 किलो
7.	11 - 12वीं	3.5 - 5 किलो

जिला परिषद CEO का पदनाम में बदलाव

राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज विभाग के अधीन जिलों में तैनात जिला परिषद मुख्य कार्यकारी के पदनाम में परिवर्तन किया गया है। अब जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस का पदनाम अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं ईजीएस एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी माडा होगा।

वन-धन योजना राज्य के माडा क्षेत्र में भी लागू

राज्य सरकार द्वारा 'वन धन योजना' को जनजाति उपयोजना क्षेत्र एवं सहरिया क्षेत्र के अलावा माडा, माडा क्लस्टर एवं बिखरी जनजाति क्षेत्रों में भी लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है।

- 'वन धन योजना' अभी जनजाति उप योजना क्षेत्र के उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही एवं सहरिया क्षेत्र के बाराँ जिलों में लागू है।
- वन धन योजना के क्रियान्वयन के लिए परियोजना अधिकारी (माडा) जिला नोडल अधिकारी (माडा क्षेत्र) होंगे तथा अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर राज्य नोडल अधिकारी होंगे।
- योजना का उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उपजों को संग्रहित करना तथा प्रशिक्षण द्वारा हित वन उपजों के मूल्य संवर्धन के लिए उपकरण उपलब्ध कराना है।
- उदयपुर जिले में 14, बाँसवाड़ा में 2, प्रतापगढ़ में 2, सिरोही में 5 तथा डूंगरपुर में 2 वन धन विकास केन्द्र कार्यरत हैं।

माडा कलस्टर योजना क्षेत्र

- ऐसे कलस्टर जिनकी कुल जनसंख्या 5,000 या इससे अधिक है तथा जिसमें 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जनजाति की है, में माडा कलस्टर योजना लागू कर विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं।
- राज्य के 8 जिलों में 11 माडा कलस्टर स्वीकृत हैं, जिसमें 159 ग्राम सम्मिलित हैं।

- जनगणना 2011 के अनुसार माडा कलस्टर क्षेत्र की जनसंख्या 1.21 लाख है, इसमें से जनजाति जनसंख्या 0.67 लाख है, जो
- कलस्टर की कुल जनसंख्या का 55.84 प्रतिशत है।

बिखरी जनजाति योजना क्षेत्र

- जनजाति उपयोजना, माडा लघु खण्ड, माडा कलस्टर एवं सहरिया क्षेत्र के अतिरिक्त 29.28 लाख जनजाति के व्यक्ति 30 जिलों में बिखरे हुए हैं।

राजस्थान सरकार का विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ MoU

29 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के मध्य एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस मीटिंग में विश्व खाद्य कार्यक्रम के भारत में निदेशक बिशो पराजुली ने भी भाग लिया था।

विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ हुई इस साझेदारी से खाद्य सुरक्षा के कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। जिनमें वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन योजना (MDM) तथा आँगनबाड़ी केन्द्रों पर चलाये जा रहे खाद्य बितरण के कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम 50 वर्षों से भारत के साथ भागीदारी निभा रहा है।

सरकारी apps एवं पोर्टल

IMPACT (Integrated Monitoring system for Pcpndt ACT) एप का शुभारंभ

11 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ.रघु शर्मा ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की निगरानी हेतु इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ पीसीपीएनडीटी एक्ट (इम्पेक्ट) एप का शुभारंभ किया।

- इम्पेक्ट एप लिंगानुपात के बढ़ रहे अंतर की गम्भीरता की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।
- इम्पेक्ट एप पीसीपीएनडीटी एक्ट में होने वाली कार्रवाई और निरीक्षण की गतिविधियों को आसान करेगी।
- इस एप के जरिए पीसीपीएनडीटी निरीक्षण रिपोर्ट को संबंधित अधिकारी निरीक्षण स्थल से तुरंत ही अपलोड कर सकते हैं। इससे रियल टाइम डाटा को मैनेज करना आसान हो जाएगा।
- इस एप को एनआईसी राजस्थान ने तैयार किया है।

ई-पेंशन तथा ई-लेखा प्रणाली का शुभारंभ

27 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वित्त विभाग द्वारा एनआईसी (NIC) के सहयोग से तैयार की गई ई-पेंशन तथा ई-लेखा प्रणाली का वर्चुअल उद्घाटन किया । ई-पेंशन से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को अपनी पेंशन स्वीकृति के लिए 40 पृष्ठों का जटिल प्रपत्र नहीं भरना होगा।

इससे सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को जटिलता भरी औपचारिकताओं से निजात मिलेगी और पेंशन स्वीकृति के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे समय की बचत होगी। साथ ही, कार्मिकों के वेतन, मेडिकल, यात्रा आदि बिलों, संवेदकों के भुगतान सहित अन्य लेखा कार्यों में सुगमता होगी।

‘शाला दर्पण’ पोर्टल का उद्घाटन

21 अक्टूबर 2020 को संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉ.सुभाष गर्ग ने शाला दर्पण पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पोर्टल के माध्यम से संस्कृत शिक्षा के कार्य सुविधा जनक एवं त्वरित गति से होंगे। पोर्टल में संस्कृत शिक्षा की सूचनाओं का ऑनलाइन अपडेशन उपलब्ध होगा। पोर्टल पर सभी विद्यार्थियों की कक्षा, वर्गवार डाटा लिया गया है एवं तत्संबंधित रिपोर्ट पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी गई है। प्रवेश, टी.सी, क्रमोन्नति प्रमाण पत्र जैसे कार्य ऑनलाइन पोर्टल से ही किए जा सकेंगे। इस पोर्टल को देववाणी एप से भी जोड़ा जायेगा।

जयपुर डिस्कॉम का ‘विजिलेंस एप’ लांच

20 नवम्बर 2020 को ऊर्जा मंत्री डॉ.बी.डी.कल्ला ने विद्युत भवन में जयपुर डिस्कॉम द्वारा तैयार ‘विजिलेंस एप’ को लांच किया। इस एप के माध्यम से विजिलेंस की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और छीजत को कम करने में भी मदद मिलेगी।

- इस ‘एप’ को विद्युत नियामक आयोग के नियमों के अनुरूप तैयार कराया गया है। इस प्रकार का ‘एप’ शीघ्र की अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम्स में भी लागू किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए डिस्कॉम द्वारा एक ‘सेल्फ बिलिंग एप’ भी तैयार कराया जा रहा है, जिसे आगामी दिनों में लांच किया जाएगा।

विजिलेंस एप के फीचर्स

- इस एप के द्वारा जांच अधिकारी जिस परिसर की जांच करेंगे वहां के ‘जिओ कॉर्डिनेट्स’ स्वतः ही एप द्वारा कैचर कर लिए जाएंगे। मौके पर लिए गए फोटो अथवा वीडियो भी इसमें स्वतः ही अपलोड हो जाएंगे। वीसीआर नंबर भी जांच स्थल पर स्वतः ही जनरेट होंगे। ऑनलाइन वीसीआर इन्द्राज होने के बाद जांच अधिकारी द्वारा बाद में इसमें किसी भी बदलाव की संभावना समाप्त हो जाएगी।
- एप में ये भी फीचर है कि मौके पर ही उपभोक्ता एवं जांच अधिकारी के हस्ताक्षर मोबाइल स्क्रीन पर लिए जा सकेंगे। विजिलेंस के सम्बंध में उपभोक्ता को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा सूचना दी जा सकेगी। ‘एप’ के माध्यम से जुर्माने की राशि का निर्धारण भी विनियामक आयोग के द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप स्वतः हो सकेगा, इसमें किसी मानवीय त्रुटि की संभावना नहीं रहेगी।

